Economics

By : Dr. Bharat Sir

पंचवर्षीय योजना

- पहली पंचवर्षीय योजना दिसंबर 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना ने एक आत्मनिर्भर बंद अर्थव्यवस्था के विचार को बढ़ावा दिया और इसे प्रो. पी. सी. महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। योजना ने डोमर द्वारा विकसित यूएसएसआर की पंचवर्षीय योजनाओं से भारी उधार लिया था। इसी कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना को डोमर महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है।
- इस योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कुल योजना बजट रु. 2069 करोड़ सात व्यापक क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए सिंचाई और ऊर्जा (27.2 प्रतिशत), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4 प्रतिशत), परिवहन और संचार (24 प्रतिशत), उद्योग (8.4 प्रतिशत), सामाजिक सेवाएं (16.64 प्रतिशत), भूमि पुनर्वास (4.1 प्रतिशत) और अन्य (2.5 प्रतिशत)। अनुकूल मानसून और अपेक्षाकृत अधिक फसल पैदावार के कारण यह योजना सफल रही।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख उल्लेखनीय बिंदुः

- पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई।
- 1956 में योजना अवधि के अंत में, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना देश में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए वित्त पोषण की देखभाल और उपाय करने के लिए की गई थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण मूल्यांकन

- स्वतंत्रता के समय भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे कि विभाजन और शरणार्थियों की आमद, गंभीर भोजन की कमी, बढती मुद्रास्फीति, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना ने समाजवादी उद्देश्य के साथ भारत को नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रवेश कराया। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना का कुल परिव्यय रु. 2069 करोड़ जिसे बाद में बढ़ाकर रु. 2378 करोड़।
- लेकिन यह योजना कमोबेश एक बेतरतीब उपक्रम थी क्योंकि उस समय कोई ठोस डेटा और विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे। यह योजना मूल रूप से इतनी सारी परियोजनाओं का एक चिथड़ा था जो एक दूसरे से अलग-थलग थी। हालांकि, दो लगातार अच्छी फसल और कृषि और सिंचाई पर जोर देने के कारण यह योजना एक बड़ी सफलता थी।
- देश लक्षित वृद्धि हासिल करने में सक्षम था और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सक्षम था। हालाँकि, प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि से ऑफसेट थी। भारत सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए WHO के साथ सहयोग किया था और इसने जनसंख्या वृद्धि में भी योगदान दिया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956 - 1961)

- प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता ने नेताओं के विश्वास को बढ़ाया। पहली योजना में कृषि विकास लक्ष्य प्राप्त किया गया था. इसलिए सरकार ने जल्दी से कृषि से परे देखना शुरू कर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग, विशेष रूप से भारी उद्योग पर केंद्रित थी । तीव्र औद्योगीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- दूसरी पंचवर्षीय योजना तथाकथित महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू के करीबी पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीयकृत यूएसएसआर मॉडल था। इस मॉडल को राज्य-निर्देशित निवेश के लिए सांख्यिकीय नींव स्थापित करने के लिए जाना जाता है और एक विस्तृत इनपुट-आउटपुट मॉडल के माध्यम से लाइसेंस राज की बौद्धिक नींव तैयार की है।
- इस मॉडल ने सुझाव दिया कि भारी उद्योगों पर जोर दिया जाना चाहिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक उच्च विकास पथ पर ले जा सकते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, इसी मॉडल पर आधारित थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख उल्लेखनीय बिंदु :

- दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों की स्थापना की गई।
- इस योजना में कोयला उत्पादन में वृद्धि और अधिक रेलवे लाइनों की शुरुआत की गई।
- परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1957 में होमी जे. भाभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किया गया था। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना एक शोध संस्थान के रूप में की गई थी।
- परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिभाशाली युवा छात्रों को खोजने के लिए 1957 में एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां

- दूसरी पंचवर्षीय योजना, समाजवादी पैटर्न पर आधारित ने तीव्र औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा था, हालांकि, प्राप्त लक्ष्य केवल 20% था। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय में केवल 8% की वृद्धि हुई।
- औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में प्रोत्साहित किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण मूल्यांकन

- दूसरी पंचवर्षीय योजना एक बड़ी छलांग थी और इसने भारी उद्योगों पर भारी जोर दिया।
- इस योजना अवधि के दौरान उद्योग नीति संकल्प में संशोधन किया गया और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ दी गई। निजी क्षेत्र कमोबेश केवल उपभोक्ता उद्योगों तक ही सीमित था।
- इस योजना के दौरान लघु और कुटीर उद्योग सुस्त रहे।
- आयात में वृद्धि हुई और बहुत कुछ और इसने भारत के स्टर्लिंग बैलेंस को उजागर कर दिया। परिणाम तीसरी योजना में देखे गए जब भारत को अपनी मुद्रा का दो बार अवमूल्यन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1901-1966)

- पहली दो योजनाओं ने देश को विकसित अर्थव्यवस्था के पथ पर ले जाने के लिए एक संस्थागत संरचना विकसित की तीसरी योजना पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के बाद उच्च उम्मीद की लहर पर सवार हुई। इस योजना में भारत ने खाद्य उत्पादन और उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया। हालाँकि, योजन अवधि में बहुत सारी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं देखी गई।
- भारत-चीन युद्ध 1962 और भारत-पाक युद्ध 1965 आदि ने देश की कमजोरी को उजागर किया। इन संघर्षो ने काफी हद तक रक्षा उत्पादन की ओर ध्यान केंद्रित किया।
- 1964 में जवाहरलाल नेहरू और उसके तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के कारण देश का मनोबल गिरा था। इसके अलावा, 1965-66 लगभग अकाल का वर्ष था, और बफर स्टॉक की कमी के कारण समस्या और अधिक गंभीर हो गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण मूल्यांकनः

- तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, देश एक उच्च बजट घाटे से जूझ रहा था। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अधिक से अधिक उधर लेने के कारण तीसरी योजना प्रभावित हुई । विदेशी सहायता बंद कर दी गई और रुपये के अवमूल्यन के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव डाला गया। 1966 में जब रुपये का अवमूल्यन किया गया, तो इसका अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव पड़ा। विकास दर 5% पर लक्षित थी, हालांकि, केवल 2.2% ही हासिल हुई। 1966 में 36% मुद्रास्फीति और रुपये के अवमूल्यन के कारण अधिकांश उपलब्धि शून्य और शून्य थी।
- कड़वे अनुभव के कारण, विभिन्न क्षेत्रों से नियोजित अवकाश की मांग उठाई गई और योजना आयोग ने स्वीकार किया कि यह योजना विफल रही। तदनुसार, सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए एक नियोजित अवकाश घोषित किया और इसके कारण, 1969 में चौथी योजना शुरू हुई। सरकार ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने और आकस्मिकता को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक स्थापित करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन जुटाए। इस तरह, अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि अल्पकालिक उद्देश्यों को लेने के लिए तीन वार्षिक योजनाओं के साथ अब नियोजन को वार्षिक बना दिया गया था।
- हालांकि, सकारात्मक उपलब्धियां भी थीं। 1965-66 के वर्षों ने भारत को हरित क्रांति और उन्नत कृषि की शुरुआत की। बांधों का निर्माण जारी रहा। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए थे। पंजाब ने बहुतायत में गेहूँ का उत्पादन शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू किए गए और राज्यों को अधिक विकास की जिम्मेदारियां दी गईं। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974)

- चौथी पंचवर्षीय योजना सूखे, अवमूल्यन और मुद्रास्फीति मंदी के दबाव के बीच इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। देश जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और बंधी हुई अर्थव्यवस्था से लड़ रहा था। इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तान (अब स्वतंत्र बांग्लादेश) की स्थिति 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के रूप में विकट होती जा रही थी । औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित धन का उपयोग युद्ध के प्रयासों के लिए किया जाना था। परिणाम यह हुआ कि यह योजना अवधि भी तीसरी पंचवर्षीय योजना से बेहतर नहीं रही।

चौथी पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख उल्लेखनीय बिंदुः

- भारत ने पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध लड़ा और बांग्लादेश के निर्माण में मदद की। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या से निपटने की आवश्यकता ।
- इस युद्ध के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ा और बैंकिंग प्रणाली में निजी बचत का अधिक से अधिक जुड़ाव शुरू हुआ।
- इस योजना के अंत में, भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया। यह परीक्षण आंशिक रूप से पश्चिम पाकिस्तान पर हमला करने और युद्ध को चौड़ा करने के खिलाफ भारत को चेतावनी देने के लिए बंगाल की खाड़ी में सातवें बेड़े की अमेरिकी तैनाती के जवाब में था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई।
- 1973 के तेल संकट ने तेल और उर्वरक की कीमतों को आसमान छू लिया जिससे मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो गई।

चौथी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण मूल्यांकन

- चौथी योजना जब इसे तीन साल के अंतराल के बाद पेश किया गया था, यह 5.5% की वृद्धि के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना थी क्योंकि पिछली योजनाओं अधिकतम 3.5% की वृद्धि लक्ष्य उपलब्धि थी।
- लेकिन भारत-पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति और बांग्लादेश शरणार्थियों की समस्या, मानसून की लगातार विफलता, 1973 के एशियाई तेल संकट ने इस योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया। तेल संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उथल-पुथल ने चौथी योजना के लिए गणनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया। इसलिए केवल 3.4% की वृद्धि हासिल की जा सकी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)

- पांचवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी।
- योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, भूमिहीनों के लिए आश्रय आदि शामिल थे। बिजली आपूर्ति अधिनियम 1975 को केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस बीच, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि देखी थी, और पांचवीं योजना के बाद से भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की।
- हरित क्रांति के असमान प्रसार की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का असफल प्रयास किया। इंदिरा गांधी सरकार ने भी इस योजना में बीस सूत्री कार्यक्रम और सिंचाई योजनाएँ जैसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया।
- हालांकि, 1975 में, इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल लगाया, और नियोजन बहुत अधिक राजनीतिकरण के अधीन हो गया। 1977 में, सरकार बदल गई और पहली गैर-कांग्रेसी सरकार ने मोरार जी देसाई के नेतृत्व में सत्ता संभाली। नई केंद्र सरकार जनता गठबंधन नामक गठबंधन थी। इस सरकार ने योजना आयोग का पुनर्गठन किया और योजना में एक नई रणनीति की घोषणा की। इस नई रणनीति में उद्देश्य और दृष्टिकोण पैटर्न में बदलाव शामिल था।
- निर्धारित किया गया नया उद्देश्य ष्सामाजिक न्याय के लिए विकास था। नया दृष्टिकोण 'रोलिंग प्लान' था। इसने 1977-78 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978-83 की अवधि के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे एक रोलिंग योजना कहा। बाद में जनता सरकार ने खुद को तबाह कर लिया और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनीं। उन्होंने जनता की रोलिंग योजना को तुरंत कूड़ेदान में फेंक दिया और 1980-85 के वर्षों के लिए अपनी योजना शुरू की। वर्ष 1978-79 को 1974ख्79 की पांचवीं योजना में वापस बहाल किया गया था।

रोलिंग योजनाएं

- जनता सरकार ने 1977-78 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978-83 की अवधि के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे एक चल योजना कहा।

रोलिंग योजना का अर्थ

- चल योजना का अर्थ यह था कि अब हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाएगी।

- चल योजनाओं में तीन प्रकार की योजनाएँ होती हैं। पहला चालू वर्ष की योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल है। दूसरा एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए एक योजना है, जो 3, 4 या 5 वर्ष हो सकती है। यह दूसरी योजना अर्थव्यवस्था (और राजनीति) की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। तीसरा एक परिप्रेक्ष्य योजना है जो 10, 15 या 20 वर्षों के लिए है। इस प्रकार, चल योजनाओं में योजना के प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में तारीखों का कोई निर्धारण नहीं है।

रोलिंग योजनाओं के लाभ और मुद्दे

- रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे लचीले होते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्यों, अनुमानों और आवंटन को संशोधित करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने में सक्षम हैं। इस प्रकार, रोलिंग योजनाएँ संशोधन और समायोजन की अनुमति देती हैं। चल योजनाओं में, किसी योजना की समीक्षा एक सतत् अभ्यास बन जाती। बदली हुई परिस्थितियों के प्रभाव और बदलती मांग और आपूर्ति की स्थिति को योजना में शामिल किया जा सकता है।
- निश्चित योजनाओं में कोई संदेह नहीं है, वार्षिक समीक्षा की जाती है, लेकिन उन्हें अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में जानकारी मिल रही है। जबकि चल योजनाओं के मामले में, वार्षिक समीक्षाएं इस प्रकार की होती हैं कि वे हर साल संशोधित नई पंचवर्षीय योजना के आधार के रूप में काम करती हैं। ऐसी वार्षिक समीक्षा रोलिंग योजनाओं का सार है।
- तथापि, यदि लक्ष्यों को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाता है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है जो पांच वर्ष की अवधि में निर्धारित किए गए हैं। बार-बार संशोधन से अर्थव्यवस्था में सही संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है जो इसके संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।
- अब तक, मेक्सिको और म्यांमार जैसी अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोलिंग योजनाएं असफल रही हैं और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, हालांकि जापान और पोलैंड जैसे विकसित देशों में उनका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

भारत की चल रही योजनाओं का भाग्य

- राजनीतिक समस्याओं के कारण, मोरार जी देसाई को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उनके उत्तराधिकारी चौधरी चरण सिंह (170 दिनों के लिए कार्यालय में थे) संसदीय बहुमत को बनाए रखने में विफल रहे क्योंकि गठबंधन सहयोगियों ने समर्थन वापस ले लिया। नए चुनाव हुए और अब इंदिरा गांधी जनवरी 1980 में प्रचंड सफलता के साथ सत्ता में वापस आई। उन्होंने अपनी रणनीति फिर से शुरू की और नई छठी योजना 1 अप्रैल 1980 को शुरू हुई, जो 31 मार्च 1985 तक जारी रही।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

- छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से, सामाजिक सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया था। इन सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, आवास और शहरी विकास और अन्य सेवाएं शामिल हैं। छठी योजना के बाद से, योजना आयोग की भूमिका और कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि हुई।
- योजना के उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और उच्च आर्थिक विकास थे। ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) आदि के माध्यम से गरीबी हटाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
- योजना की शुरुआत में गरीबी 47% थी और इसे प्राप्त करने के लिए 30% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस समय हासिल किया गया वास्तविक लक्ष्य 37 फीसदी था।
- स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (TRYSEM) 1979 में शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NRE) अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था और अप्रैल 1981 से एक नियमित योजना कार्यक्रम बन गया
- अभी तक भारत की 37 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, जो अब सरकार के अनुसार घटकर 20.9 प्रतिशत हो गई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

- 1985-2000 के लिए एक दीर्घकालिक योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी और 9 नवंबर, 1985 को इस पृष्ठभूमि में 7वीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई थी। यह योजना राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी जब डॉ मनमोहन सिंह योजना के उपाध्यक्ष थे। आयोग मूल उद्देश्य थे: त्वरित विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) की निरंतरता और विस्तार की भी परिकल्पना की गई थी, जिसे छठी योजना में शुरू किया गया था।
- सातवीं पंचवर्षीय योजना काफी बड़ी थी। रुपये का परिव्यय। 1,80,000 करोड़ न केवल पिछली योजना का दोगुना था, बल्कि इसका व्यापक दायरा और रुपये का वास्तविक खर्च भी था। 218700 करोड़ योजना परिव्यय से 21.5% अधिक था। इस योजना में ग्रामीण विकास पर परिव्यय को दोगुना कर दिया गया था।

वार्षिक योजनाएँ: 1990-92

- 1980 के दशक के अस्थिर राजकोषीय घाटे के साथ-साथ अत्यधिक बाहरी उधारी जमा हुई और 1991 के संकट में समाप्त हुई। जनवरी 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार केवल एक अरब डॉलर रह गया था, जो तीन सप्ताह के आयात के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त था।
- इस प्रकार, देश अपने बाहरी दायित्वों पर चूक के कगार पर था। चंद्रशेखर के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया थी कि भारत के 67 टन सोने के भंडार को गिरवी रखकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.2 बिलियन डॉलर का आपातकालीन ऋण प्राप्त किया जाए। इससे देश के शासकों के खिलाफ राष्ट्रीय भावनाओं की लहर दौड़ गई।
- 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद, एक राष्ट्रव्यापी सहानुभूति लहर ने कांग्रेस की जीत हासिल की। नए प्रधानमंत्री नरसिंहराव थे और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। इस नई सरकार ने कई सुधार शुरू किए जिन्हें सामूहिक रूप से 'उदारीकरण' कहा जाता है। इस प्रक्रिया ने देश को फिर से पटरी पर ला दिया और उसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना क्रूर स्तर कभी नहीं छुआ।
- 1990-92 की अवधि के दौरान 1990-91 और 1991-92 के लिए दो वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। वे रुपये के लायक थे। 58,369.30 करोड़ और रु। 64,751.20 करोड़। 1990-92 के दौरान देश में राजनीतिक-आर्थिक उथल-पुथल के कारण आठवीं योजना शुरू नहीं हो सकी ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)

- केंद्र में राजनीतिक उथल-पुथल के साथ-साथ 80 के दशक के अंत में देश के वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और राजकोषीय असंतुलन के कारण, आठवीं योजना 1990 में शुरू नहीं हो सकी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना के प्रारूप की पुष्टि की। यह निर्णय लिया गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1992 को शुरू होगी, और 1990-91 और 1991-92 को 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 के पहले के दृष्टिकोण के ढांचे के भीतर तैयार की गई अलग-अलग वार्षिक योजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए -

प्रमुख उद्देश्य

- रोजगार का सृजन, जनसंख्या वृद्धि और समग्र मानव विकास की जांच करना।
- सभी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल और टीकाकरण।
- कृषि गतिविधियों का विकास और विविधीकरण।
- बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- 8वीं योजना सांकेतिक योजना के माध्यम से एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रबंधन की योजना थी। 1992 तक भारत विश्व व्यापार संगठन का एक पक्ष था, और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय बढ़ते घाटे और विदेशी ऋण को ठीक करने के लिए लिया गया था।

महत्वपूर्ण अवलोकन

- आठवीं पंचवर्षीय योजना को ''राव और मनमोहन योजना'' कहा जा सकता है। यह एक सुधार काल था और निम्नलिखित सुधार काल के दौरान हुआ। 1991 में रुपये का एक बार फिर अवमूल्यन हुआ। मुद्रा अवमूल्यन के कारण, भारतीय रुपया 1991 में 17.50 प्रति डॉलर से गिरकर 1992 में 45 प्रति डॉलर हो गया।
- रुपये का मूल्य 23% अवमूल्यन किया गया था। सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके तहत उसने अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया, आयात शुल्कों को कम कर दिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार खोल दिए, बाजार-निर्धारित विनिमय दर प्रणाली की शुरुआत की।
- आठवीं योजना अप्रैल 1992 में शुरू हुई। प्रमुख आकर्षण में से एक उद्योगों का आधुनिकीकरण था। यह योजना गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी।
- इस योजना अवधि में कई प्रमुख कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले हासिल की गई विकास दर 6.8% थी। पहले दो वर्षों में, हासिल की गई विकास दर 7.7% थी। बाद में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते दबाव के कारण इसमें कमी आई जो बाद में 1997 के एशियाई वित्तीय संकट में समाप्त हुई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997 - 2002)

- इस अवधि में सरकार में बदलाव देखा गया। नौवीं योजना ''सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास'' के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसने कृषि विकास को भी महत्व दिया। सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ऋण कार्यक्रमों के नियमन पर जोर दिया गया। इसे सरकार की नीति के 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित किया गया था:
  - जीवन की गुणवत्ता में सुधार
  - उत्पादक रोजगार का सृजन
  - क्षेत्रीय संतुलन बनाना आत्मनिर्भरता
- औसत लक्ष्य वृद्धि दर 6.5% थी लेकिन प्राप्त वृद्धि दर 5.5% थी। कृषि में वृद्धि 2.1% तक गिर गई और विनिर्माण 4.69% से गिरकर 4.51% और पिछली योजनाओं से 7.57% हो गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)

- दसवीं योजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2002 को शुरू की गई थी। यह योजना उदारीकरण के बाद प्राप्त बेहतर विकास दर से उत्पन्न उच्च उम्मीदों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) में अर्थव्यवस्था में 7.7% की औसत वृद्धि दर्ज की गई, जो अब तक किसी भी योजना अवधि में सबसे अधिक है।
- राष्ट्रीय आय में 7.6% और प्रति व्यक्ति आय में 6% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन 8.6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। योजना के अंतिम वर्ष में दो अंकों की वृद्धि हासिल की गई। इसने वाजपेयी सरकार को 2004 में अपने निर्धारित समय से थोड़ा पहले एक नया चुनाव बुलाने के लिए प्रेरित किया।
- एनडीए ने ''फील-गुड फैक्टर'' के नाम पर वोट देने के लिए कहा, लेकिन किसी तरह यह काम नहीं किया। वाजपेयी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और केंद्र में यूपीए-1 की सरकार आई। 2004-05 के लिए एनएसएसओ की 61वीं रिपोर्ट में 26.1% के पहले के स्तर से 22% गरीबी दर्ज की गई। यूपीए सरकार ने एनडीए की कई योजनाओं को जारी रखा। इसने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए भारत निर्माण शुरू किया।

11वीं पंचवर्षीय योजना

- भारत ने ग्यारहवीं योजना अवधि में आर्थिक विकास के प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ प्रवेश किया। 10वीं योजना की प्रगति के साथ, भारत 11वीं योजना के शुरुआती वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा।
- भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे में कई आयामों में सुधार हो रहा है, और यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि 2011-12 में मंदी के बावजूद, ग्यारहवीं योजना अवधि में अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन 8 प्रतिशत थी। यह 9 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से कम था, लेकिन दसवीं योजना में 7.8 प्रतिशत की उपलब्धि से बेहतर था।

12वीं पंचवर्षीय योजना

- भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य विषय ''तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास'' है।
- भारत सरकार की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 27 दिसंबर 2012 को बारहवीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी।
- सरकार का इरादा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10: तक कम करने का है। योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए राष्ट्र की ढांचागत परियोजनाओं को बेहतर बनाना है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत विकास में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निजी निवेश को आकर्षित करना है, जो सरकार के सब्सिडी बोझ को 2 से 1.5 प्रतिशत तक कम करना सुनिश्चित करेगा। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का प्रतिशत।
- यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या) योजना में सब्सिडी के नकद हस्तांतरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे:
- गैर-कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना।
- स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करने के लिए। उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए।
- 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो। हरित क्षेत्र को हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना।
- 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।